



IAS/PCS/PCS(J)

Estd :1988

डेली करेंट अफेयर्स जून-2019

(6th June)

Topic: For prelims and mains:

राजकोषीय प्रदर्शन सूचकांक है :

समाचार में क्यों? भारतीय उद्योग परिसंघ (**Confederation of Indian Industry-CII**) ने केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत बजट की गुणवत्ता का आकलन करने के लिये एक राजकोषीय प्रदर्शन सूचकांक (**Fiscal Performance Index**) पेश किया है।

CII के कार्य :

- ✓ **CII** एक गैर-सरकारी, लाभ-रहित, उद्योग-आधारित और उद्योग-प्रबंधित संगठन है।
- ✓ **सीआईआई** नीतिगत मुद्दों पर सरकार के साथ काम करता है।
- ✓ **सीआईआई** भारतीय उद्योग और **अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समुदाय** के लिए एक संदर्भ बिंदु के रूप में कार्य करता है।

सूचकांक के घटक

- ✓ राजस्व व्यय के गुणात्मक मूल्यांकन
- ✓ पूंजीगत व्यय
- ✓ राजस्व
- ✓ राजकोषीय विवेक (प्रूडेंस) और सार्वजनिक ऋण का स्तर।

मुख्य निष्कर्ष :

- CII ने 2004-05 से 2016-17 तक राज्य और केंद्रीय बजट का विश्लेषण करने के लिए इस सूचकांक का उपयोग किया है।
- **FY13 और FY18 के बीच राजकोषीय घाटे में कमी के बावजूद बजट का समग्र प्रदर्शन केवल FY16 और FY17 में सुधार के साथ स्थिर रहा है।**
- यह काफी हद तक राजस्व, **पूंजीगत व्यय और शुद्ध कर राजस्व सूचकांकों में मॉडरेशन के कारण है।**
- राजस्व और पूंजीगत व्यय सूचकांकों में सुधार के कारण राजकोषीय घाटे की संख्या में गिरावट के बावजूद सभी राज्य बजटों के संयोजन में सुधार हुआ है।
- **गुजरात, हरियाणा और महाराष्ट्र** सहित अविश्वसनीय रूप से उच्च आय वाले राज्य जो कि राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए जीडीपी अनुपात के कारण अच्छा राजकोषीय स्वास्थ्य होने का अनुमान लगाते हैं, अन्य राज्यों की तुलना में **खराब व्यय और राजस्व गुणवत्ता** के कारण समग्र एफपीआई पर अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं।
- राजस्व और पूंजीगत व्यय सूचकांकों में अच्छे प्रदर्शन के कारण **मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार** सहित अन्य राज्यों ने **एफपीआई** पर अच्छा प्रदर्शन किया है।

FPI की आवश्यकता :

- एकल मानदंड जैसे कि राजकोषीय घाटा जीडीपी अनुपात के लिए **‘हमें बजट की गुणवत्ता के बारे में कुछ नहीं बताता है।**
- इसलिए, सरकार को एकल संकेतक के **बजाय केंद्र और राज्य स्तर पर बजट की गुणवत्ता** को मापने के लिए कई संकेतकों का उपयोग करना चाहिए।

आगे का रास्ता- सीआईआई की सिफारिशें :

- सरकार को कर आधार को व्यापक बनाने, **शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में निवेश बढ़ाने के साथ-साथ परिसंपत्तियों के स्वरूपाव और साथ ही बुनियादी ढांचे, किम्वयती आवास में निवेश बढ़ाने और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को प्रोत्साहित** करने के लिए भी सरकार को लाभांश सीमित करके पूंजीगत व्यय बढ़ाने के लिए प्रयास करना चाहिए।
- **राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (Fiscal Responsibility and Budget Management-FRBM) अधिनियम**, जो राजकोषीय घाटे को कम करने हेतु सरकारों के लिये लक्ष्य निर्धारित करता है, को **केवल एक घटक पर ध्यान केंद्रित** नहीं करना चाहिये।
- इसके बजाय इस अधिनियम के अंतर्गत सभी संस्थाओं के समग्र प्रदर्शन पर व्यय गुणवत्ता, **राजस्व प्राप्तियों की गुणवत्ता, और राजकोषीय समझदारी (Fiscal Prudence)** के दृष्टिकोण से आकलन किया जाना चाहिये।

Topic: For prelims and mains:

आर्थिक जनगणना-2019 :

समाचार में क्यों? 7वीं आर्थिक जनगणना (Seventh Economic Census-7th EC) की तैयारियाँ प्रगति पर हैं। **आर्थिक जनगणना के तहत छोटे और घरेलू स्तर पर होने वाली आर्थिक गतिविधियों के साथ ही सभी आर्थिक इकाइयों/प्रतिष्ठानों की गणना की जाएगी।**

देश भर में गणनाकारों द्वारा शुरू किये जाने वाले **क्षेत्र कार्य (Field Work)** की तैयारी के लिये सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (Ministry of Statistics and Program Implementation) द्वारा कई कार्यकलापों की योजना तैयार की गई है।

आर्थिक जनगणना के बारे में :

- आर्थिक जनगणना भारत की भौगोलिक सीमाओं के भीतर स्थित सभी प्रतिष्ठानों का संपूर्ण विवरण है।
- आर्थिक जनगणना देश के **सभी प्रतिष्ठानों के विभिन्न संचालनगत एवं संचयनगत परिवर्तन कारकों पर भिन्न-भिन्न** प्रकार की सूचनाएँ उपलब्ध कराती है।
- आर्थिक जनगणना देश में सभी आर्थिक प्रतिष्ठानों की आर्थिक गतिविधियों के भौगोलिक **विस्तार/क्लस्टरों, स्वामित्व पद्धति** जुड़े हुए व्यक्तियों इत्यादि के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी भी उपलब्ध कराती है।
- आर्थिक जनगणना के दौरान संग्रहित सूचना राज्य एवं जिला **स्तरों पर सामाजिक-आर्थिक विकास संबंधी** योजना निर्माण के लिये उपयोगी होती है।

आर्थिक जनगणना-2019 :

- **वर्ष 2019 में 7वीं आर्थिक जनगणना** का संचालन सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है।
- वर्तमान आर्थिक जनगणना में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने **7वीं आर्थिक जनगणना के लिये कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय** के तहत एक स्पेशल पर्पज

व्हिकल्स, कॉमन सर्विस सेंटर ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड (Common Service Center e&Governance Services India Limited) के साथ साझेदारी की है।

- **7वीं आर्थिक जनगणना में आँकड़ों के संग्रहण, सत्यापन**, रिपोर्ट सृजन एवं प्रसार के लिये एक आईटी आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाएगा।
- 7वीं आर्थिक जनगणना के परिणामों को प्रक्षेत्र कार्य के प्रमाणन एवं सत्यापन के बाद उपलब्ध कराया जाएगा।
- आर्थिक जनगणना के तहत गैर-फार्म कृषि एवं गैर-कृषि क्षेत्र में वस्तुओं/सेवाओं **(स्वयं के उपयोग के एकमात्र प्रयोजन के अतिरिक्त)** के उत्पादन या वितरण में जुड़े घरेलू उद्यमों सहित सभी प्रतिष्ठानों को शामिल किया जाएगा।

पुरानी आर्थिक जनगणना :

- अभी तक केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने **6 आर्थिक जनगणनाएँ (Economic censuses) संचालित की हैं।**
 - पहली आर्थिक जनगणना, वर्ष 1977 में
 - दूसरी आर्थिक जनगणना, वर्ष 1980 में
 - तीसरी आर्थिक जनगणना, वर्ष 1990 में
 - चौथी आर्थिक जनगणना, वर्ष 1998 में
 - पाँचवीं आर्थिक जनगणना, वर्ष 2005 में
 - छठी आर्थिक जनगणना, वर्ष 2013 में

कॉमन सर्विस सेंटर ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड (CSC e-Governance Services India Limited)

- **CSC ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड को कंपनी अधिनियम, 1956** के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया है जिसका उद्देश्य CSC योजना के कार्यान्वयन की निगरानी करना है।
- योजना को प्रणालीगत व्यवहार्यता और स्थिरता प्रदान करने के अलावा यह CSC के माध्यम से नागरिकों को सेवाओं की डिलीवरी हेतु एक केंद्रीकृत और सहयोगी रूपरेखा भी प्रदान करता है।

Topic: For prelims and mains:

विश्व पर्यावरण दिवस :

समाचार में क्यों? पर्यावरण की रक्षा हेतु दुनिया भर में जागरूकता और कार्रवाई को प्रोत्साहित करने के लिये प्रत्येक **वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस (World Environment Day) मनाया जाता है।**

महत्वपूर्ण तथ्य

- इस कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष **1972 में खराब पर्यावरणीय परिस्थितियों** और उसके बढ़ते दुष्प्रभाव के बारे में जागरूकता फैलाने के लिये की गई थी। वर्तमान में यह प्रदूषण की समस्या पर चर्चा करने के लिये एक **वैश्विक मंच बन गया है तथा 100 से अधिक देशों में इसका आयोजन किया जाता है।**
- इस बार पर्यावरण दिवस की थीम **'वायु प्रदूषण' (Air Pollution)** है तथा इसका वैश्विक मेजबान चीन है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2018 में भारत ने **'बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन (Beat Plastic Pollution)** थीम के साथ विश्व पर्यावरण दिवस के **अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम की मेजबानी की थी।**
- सरकार ने विश्व पर्यावरण दिवस समारोह के हिस्से के रूप में **#SelfiewithSapling** नाम से एक अभियान शुरू किया है तथा लोगों से एक पौधा लगाने और सोशल मीडिया पर इसके साथ एक सेल्फी पोस्ट करने का आग्रह किया गया है।

वायु प्रदूषण (Air Pollution) :

- वायु (**प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम, 1981** **छाप्त (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981**, 'वायु प्रदूषक' को वातावरण में मौजूद किसी भी ठोस, तरल या गैसीय पदार्थ के रूप में परिभाषित करता है, जो मनुष्य या अन्य जीवित प्राणियों या पौधों या संपत्ति या वातावरण के लिये हानिकारक हो सकता है।
- वायु प्रदूषण हार्ट अटैक अथवा हृदयघात के कारण होने वाली मौतों में से **एक चौथाई मौतों तथा स्ट्रोक, श्वसन संबंधी बीमारियों, फेफड़ों के कैंसर के कारण होने वाली कुल मौतों में से एक तिहाई के लिये जिम्मेदार है।** वायु प्रदूषण जलवायु को भी प्रमुखता से प्रभावित करता है, जिसका दुष्प्रभाव संपूर्ण पृथ्वी की कार्यप्रणाली पर परिलक्षित होता है।
- दुनिया भर में **लगभग 92 प्रतिशत लोग दूषित हवा में सांस लेने को विवश है।** वायु प्रदूषण के कारण हर साल स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर 5 ट्रिलियन डॉलर का बोझ पड़ता है।
- **सतही ओजोन प्रदूषण (Ground-level ozone pollution) के कारण वर्ष 2030 तक फसलों की पैदावार लगभग 26 प्रतिशत तक कम होने की उम्मीद जताई जा रही है।**
- हाल ही में भारत ने **राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (National Clean Air Programme- NCAP) का प्रारम्भ तैयार कर इसे लॉन्च किया,** जिसका उद्देश्य वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क को बढ़ाने के अलावा वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और उन्मूलन करना है।

वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 :

- वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और उन्मूलन के उद्देश्य से वर्ष 1981 में संसद द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम लागू किया गया।
- अधिनियम में शीर्ष स्तर पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (Central Pollution Control Board-CPCB) की स्थापना और राज्य स्तर पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (State Pollution Control Boards-SPCB) को वायु गुणवत्ता में सुधार नियंत्रण एवं वायु प्रदूषण के उन्मूलन से संबंधित किसी भी मामले पर सरकार को सलाह देने का प्रावधान किया गया है।
- CPCB वायु की गुणवत्ता के लिये मानक भी तय करता है।

प्रतिष्ठा के लिए तथ्य

❖ जन शिक्षण संस्थान

- कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तत्त्वावधान में चल रहे जन शिक्षण संस्थानों (Jan Shikshan Sansthan) के अंतर्गत **व्यावसायिक प्रशिक्षण ले रहे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिये फीस माफ कर दी गई है।**
- जन शिक्षण संस्थान इससे पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत था, **जिसे वर्ष 2018 में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय** को हस्तांतरित कर दिया गया।

जन शिक्षण संस्थान क्या है:

- जन शिक्षण संस्थान (Jan Shikshan Sansthan) की स्थापना कौशल प्रशिक्षण और सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े एवं शिक्षा की दृष्टि से वंचित समूहों **जैसे- नव-समूहों, अर्द्धशिक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं तथा लड़कियों, मलिन बस्तियों में रहने वालों,** पलायन करके आए श्रमिकों के बीच उद्यमिता के अवसर शुरू करने में मदद करने हेतु की जाती है।

❖ गंगा क्वेस्ट पुरस्कार 2019 :

- 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर **स्वच्छ गंगा के लिये राष्ट्रीय मिशन (NMCG) ने गंगा और उसकी सहायक नदियों** के संरक्षण के तरीकों पर चर्चा करने के लिये एकदिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया।
- इस अवसर पर गंगा क्वेस्ट, 2019 के विजेताओं को पुरस्कार भी प्रदान किये गए।

- **NMCG** ने **नमामि गंगे कार्यक्रम में सर्वजनिक भागीदारी को बढ़ाने और युवाओं** को प्रोत्साहित करने के लिये एक **अखिल भारतीय गंगा क्वेस्ट 2019** का आयोजन किया था।
- यह गंगा नदी पर पहली राष्ट्रीय स्तर ली ऑनलाइन क्विज है।
- गंगा नदी के बारे में जागरूकता और ज्ञान प्रसार के लिये एक महीने तक ऑनलाइन क्विज आयोजित की गई।
- यह **क्विज 22 अप्रैल 2019 (विश्व पृथ्वी दिवस) को शुरू की गई और 22 मई 2019 (विश्व जैव विविधता दिवस)** को समाप्त हुई।
- NMCG द्वारा यह **आयोजन वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (Wild Life Institute of India), फ्री क्रेज फाउंडेशन (Free Craze foundation), GIZ और VA Tech WABAG** की साझेदारी में किया गया।

स्वच्छ गंगा के लिये राष्ट्रीय मिशन (NMCG)

- स्वच्छ गंगा के लिये राष्ट्रीय मिशन राष्ट्रीय स्वच्छ मिशन (NMCG) को 12 अगस्त, 2011 को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया था।
- इसका कार्यान्वयन जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय के अंतर्गत किया जाता है।

LUCKNOW

IAS/PCS/PCS(J)